क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 146, बुधवार, 20 जून 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

केजरीवाल करें खालिस्तान पर अपना स्टैंड स्पष्ट

खैहरा पर बरसी हरसिमरत कहा- मुख्यमंत्री केजरीवाल करें खालिस्तान पर अपना स्टैंड स्पष्ट

चंडीगढ़।

विवादों में घिरे रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने निशाना साधा है। हरसिमरत का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता बेवजह मुद्दों को तूल दे रहे हैं, एक तरफ केजरीवाल और उनके मंत्री उपराज्यपाल और कार्यालय में धरने देकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब में विधानसभा विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैहरा खालिस्तान समर्थक बयान देकर राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे है। कैंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप को मिल रही फंडिंग की जांच कराई जाए। खैहरा द्वारा खालिस्तान के समर्थन में दिए गए बयान पर केजरीवाल अपना बयान स्पष्ट करें। खैहरा उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो देश को बांटना चाह रहे है। केजरीवाल ने अभी तक इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा, खैहरा कौन से डॉलर की भाषा बोल रहा हैं? ये डालकर किस देश का और किस आतंकी संगठन का है? यह देखना हैं और उसकी जांच होनी चाहिए।

भविष्य निधि से निकासी पर अंकुश लगाने की तैयारी

भविष्य निधि से निकासी पर अंकुश लगाना चाहती है मोदी सरकार: कांग्रेस

नेशनल डेस्क।

कांग्रेस ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती करने के बाद अब भविष्य निधि से निकासी पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि भविष्य निधि पर ब्याज दर कम करने के बाद मोदी सरकार अब निकासी की सीमा पर अंकुश लगाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह मोदी जी के लिए 'जीत' होगी और हर कर्मचारी के लिए 'हार' होगी। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी के लिए 'जीत' का मतलब है कि नौकरियों के आंकड़े में बढ़ोतरी दिखाना है जो 'एक और जुमला' होगा। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी के लिए 'हार' का मतलब यह होगा कि ईमानदार करदाताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा में कटौती की जाएगी। कांग्रेस नेता ने जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है उसके मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 'सामाजिक सुरक्षा कवर' की शुरुआत करने की तैयारी में है और इसके तहत नौकरी जाने की स्थिति में भी कोई कर्मचारी अपनी भविष्य निधि से पैसा आंशिक तौर पर निकाल पाएगा।

छत्तीसगढ़: नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी घायल

नेशनल डेस्क। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस अधिकारी समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांकेर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तमोरा गांव के जंगल में बीती रात मुठभेड़ के दौरान जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के एक उप निरीक्षक और एक जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पड़ोसी जिले नारायणपुर के एड़का थाना क्षेत्र से डीआरजी के दल को गस्त में रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस दल जब कांकेर जिले के तमोरा गांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की। नक्सली गोलीबारी में डीआरजी के उप निरीक्षक सुक्कू राम नुरेटी और हवलदार परेश्वर गावड़े घायल हो गए। वहीं कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस दल को रवाना किया गया और घायल पुलिसकर्मियों को वहां से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि पुलिस दल ने मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है।

डोकलाम जैसा दूसरा तनाव नहीं झेल सकते भारत -चीन

नई दिल्ली। डोकलाम मुद्दे पर तनावपूर्ण परिस्थितियां झेल चुके भारत व चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने एक बैठक में सीमा विवाद का 'परस्पर स्वीकार्य हल' तलाशे जाने की जरूरत पर भी बल दिया। भारत में चीन के राजदूत ल्यू झाओहुई ने सोमवार को कहा कि भारत और चीन का द्विपक्षीय संबंध अब डोकलाम जैसा कोई दूसरा तनाव नहीं झेल सकते। ल्यू झाओहुई 'बियांड वुहान- हाऊ फार एंड फास्ट कैन चाइना-इंडिया रिलेशन गो' विषय पर यहां चीनी दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 'कुछ भारतीय मित्रों' ने भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय सम्मेलन का सुझाव दिया है जो बहुत उम्दा विचार है। यदि चीन, रूस और मंगोलिया के बीच त्रिपक्षीय सम्मेलन संभव है तो चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसा क्यों नहीं सकता है। भारत और चीन के संबंधों पर चीनी राजदूत कहा कि सीमा विवाद को इतिहास पर छोड़ देना चाहिए। मतभेद स्वाभाविक है लेकिन इन्हें आपसी सहयोग बढ़ाकर नियंत्रित किया सकता है। हमें विशेष प्रतिनिधियों की बैठक के जरिए आपसी विश्वास बढ़ाने के उपायों को अपना कर परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशना चाहिए। हम एक और दोकलम खड़ा नहीं कर सकते।

शुजात बुखारी को हो गया था हत्या का अंदेशा, महबूबा से की थी सुरक्षा बढ़ाने की मांग

लंदन।

खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व विशेष निदेशक ए.एस. दुलत ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी ने कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से संपर्क किया था। बुखारी की पिछले हफ्ते श्रीनगर में हत्या कर दी गयी। दैनिक अखबार 'राइजिंग कश्मीर' के प्रधान संपादक बुखारी की 14 जून को श्रीनगर में उनके कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निजी सुरक्षा गार्ड के तौर पर उन्हें उपलब्ध कराए गए दो पुलिस अधिकारी भी इस हमले में मारे गए थे। सरकार ने इन हत्याओं के लिए कश्मीर में आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था। पिछले हफ्ते यहां पहुंचे दुलत ने एक बयान में कहा कि उन्होंने (बुखारी ने) बार-बार अलगाववाद, आतंकवाद में वृद्धि और व्यापक डर की बार-बार चेतावनी दी थी और कहा था कि ऐसे माहौल में कोई भी सुरक्षित नहीं है।'' दुलत ने कहा कि बुखारी ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग के साथ कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से संपर्क किया था। किसने सोचा था कि यह भद्र व्यक्ति निशाना बन सकता है। पूर्व खुफिया प्रमुख ने कहा, ''छह हफ्ते पहले इस्तांबुल में हमारी भेंट हुई थी जहां से उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की थी। एक पखवाड़े से अधिक समय तक यात्रा करने के बावजूद वह 23 मई को मेरी पुस्तक 'द स्पाई क्रोनिकल्स' के लोकार्पण के मौके पर श्रीनगर से दिल्ली आए। उन्होंने कहा कि बुखारी इस बात के प्रबल पक्षधर थे कि वार्ता ही इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है।

दाती महाराज ने क्राइम ब्रांच ऑफिस में किया सरेंडर, हो रही है कड़ी पूछताछ

नई दिल्ली।

अपने आश्रम की शिष्या से दुष्कर्म करने का आरोप झेल रहे शनिधाम संस्थान के संस्थापक दाती महाराज उर्फ मदनलाल ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में समर्पण कर दिया है। कोर्ट की ओर से उन्हें सरेंडर करने का कल आखिरी दिन था। हालांकि वह न तो कल पुलिस के सामने पेश हुए और ना ही उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि दाती महाराज के वकील ने क्राइम ब्रांच को सूचित किया था कि उन्हें बुधवार तक का वक्त दिया गया है। अगर दाती मदन समर्पण नहीं करते तो कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होना लाजिमी था। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दाती मदन और उसके तीनों साथी आरोपी भाई अनिल, अशोक और अर्जुन ने पहले भी 2 बार सामने आकर जांच में सहयोग करने की बात कही थी। लेकिन दोनों बार वे पेश नहीं हुए। दाती मदन और उनके तीनों साथी आरोपी भाईयों की धरपकड़ के लिए क्राइम ब्रांच की 15 सदस्यीय टीम ने रविवार को दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी की और उनके आश्रम से अहम सबूत भी जुटाए। एसीपी रितेश कुमार के नेतृत्व में राजस्थान के पाली आश्रम गई थी। लेकिन, दाती मदन उससे पहले ही अपने आरोपी भाइयों के साथ रफू चक्कर हो गया था।

स्टेट बैंक के एटीएम में चूहों ने कुतर डाले 12 लाख के नोट, मशीन खुलते ही चौंक गए लोग

नई दिल्ली।

देश में पहले एटीएम के कैश की कमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही वहीं असम के तिनसुकिया में चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के एटीएम में चूहों ने 10 या 20 हजार रुपए नहीं, बल्कि पूरे 12 लाख रुपए के नोट कुतर डाले। इस पूरी घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस घटना का खुलासा उस समय हुआ जब जब कर्मचारी बंद मशीन को ठीक करने पहुंचे। बैंक का कहना है कि चूहों ने 12.38 लाख रुपए के नोट नष्ट कर दिए हैं। गुवाहाटी की एक फाइनैंशल कंपनी एफआईएस- गलोबल बिजनस सल्यूशन इस एटीएम की देख-रेख और इसमें कैश डिपॉजिट का काम करती है। कंपनी के मुताबिक 19 मई को एटीएम में 29 लाख रुपये जमा किए गए थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई को ही एटीएम ने काम करना बंद कर दिया। मीडिया से बातचीत में एक बैंक अधिकारी ने बताया कि करीब 17 लाख की करंसी को नुकसान होने से बचा लिया गया है। हालांकि एटीएम के अंदर नोटों के नष्ट होने की असल वजह चूहे हैं या कुछ और यह इस बात की अभी पता नहीं चल पाया है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस अब मामलें की जांच में जुटी हुई है।

विमानों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि इन पर मिसाइली हमले का भी असर नहीं होगा।

आसमान में भी मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अपग्रेड होगा प्रधानमंत्री का विमान

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों के समय सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया जा रहा है। जमीन पर तो मोदी की सुरक्षा काफी मजबूत है, अब आसमान में भी इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री जिस विमान से विदेशी दौरों पर जाते हैं, उसे अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार मोदी के विमान 1,100 करोड़ रुपए खर्च कर दो नए बोइंग 777 विमानों को पूरी तरह वीवीआईपी बनाया जाएगा। विमानों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि इन पर मिसाइली हमले का भी असर नहीं होगा।

एयर इंडिया ने सिएटल स्थित विमान निर्माता से प्राप्त इन दो नए बोइंग 777 विमानों को वापस अमेरिका भेजकर 1,100 करोड़ रु. के खर्च से उसे वीवीआईपी के अनुरूप बनाने के लिए कहा है। इस विमान में मिसाइल हमले को नाकाम करने के अलावा मिसाइल का ध्यान भटकाने वाली तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

पीएम मोदी जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई सुविधाएं हैं। विमान में कांफ्रेंस रूम, वीआईपी गेस्ट के लिए सिटिंग एरिया, एक ऑफिस और आराम करने के लिए प्राइवेट रूम तक उपलब्ध है। इतना ही नहीं ऑफिस का काम निपटाने तक की सभी सुविधाएं इस विमान में मौजूद हैं। एक बोइंग 777-300 ईआर विमान में अमूमन 342 सीटें होती हैं, जिनमें 4 फर्स्ट क्लास, 35 बिजनेस क्लास और 303 इकोनॉमी क्लास की सीटें होती है।

ओडिशा के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे नवीन पटनायक

भुवनेश्वर।

बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रमशः नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू के बाद अब नवीन पटनायक ने पिछड़ेपन और अनुसूचित जाति , जनजाति जनसंख्या के अधिक प्रतिशत का हवाला देते हुए एक बार फिर ओडिशा के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। पटनायक रविवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की चौथी संचालन परिषद बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष राज्य का दर्जा सहित राज्य की विभिन्न मांगों से अवगत कराया है। सोलह जून को लिखा गया पत्र सोमवार को मीडिया को उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई। पटनायक द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराने को 2019 में आम चुनावों तथा ओडिशा विधानसभा से पहले बीजद के राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। पटनायक ने पत्र में कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अधिक प्रतिशत और राज्य के बार बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बीच, ओडिशा अपने विकास की तेज रफ्तार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का हकदार है और उसके साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए पूर्वोत्तर और हिमालय पर बसे राज्यों के समान व्यवहार होना चाहिए। इस बीच , पटनायक ने राज्य सरकार के अधिकारियों से संभावित आपदा के लिए तैयार रहने को कहा क्योंकि मानसून राज्य में पहुंच चुका है। उन्होंने संबंधित विभागों से पूर्व चेतावनी प्रणाली , बचाव एवं राहत अभियान , पेयजल आपूर्ति , स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय करने को कहा।

संक्षिप्त समाचार

आप आरोप- मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे अनिल बैजल

नेशनल डेस्क। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) ने उप-राज्यपाल अनिल बैजल पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि बैजल केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और इस साल की शुरुआत में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हुए कथित हमले के बाद पैदा हुए गतिरोध को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार एवं आईएएस अधिकारियों की बैठक नहीं बुला रहे हैं। ' आप ' के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दावा किया कि आईएएस अधिकारी सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी और सरकार दोनों गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उप- राज्यपाल बैठक नहीं बुला रहे, जिससे हमारा आरोप साबित होता है कि वह नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह नवाज शरीफ से मिल सकते हैं लेकिन पिछले आठ दिनों से एलजी दफ्तर में धरना पर बैठे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। ' आप ' नेता ने दावा किया कि एलजी ने बैठक बुलाने के लिए उप-मुख्यमंत्री की तरफ से लिखे गए पत्र का जवाब नहीं दिया, जो दिखाता है कि वह अपने मन से काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि (आजादी से पहले) वायसराय एलजी हाउस में रहते थे, जहां अब बैजल रहते हैं। ऐसा लगता है कि वायसराय की आत्मा उनमें समा गई है। सिंह ने मांग की कि एलजी चार महीने से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द बैठक बुलाएं।' आप ' के प्रवक्ता दिलीप पांडेय ने दावा किया कि आईएएस अधिकारियों ने निजी बातचीत में काम पर आने की अच्छा जाहिर की है लेकिन वे एलजी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने तक आईएएस अधिकारी अपनी इच्छा के बावजूद काम पर नहीं लौट सकते।

सेना प्रमुख ने राइफलमैन औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की, बंधाया ढांढस

जम्मू । सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज शहीद राइफलमैन औरंगजेब के माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर उनका दुख सांझा करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। पिछले सप्ताह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने औरंगजेब को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनरल रावत पुंछ जिले के सुदूरवर्ती सलानी गांव गए और शहीद राइफलमैन के परिवार को इस बात से अवगत करवाया कि बल दुख की इस घड़ी में उनके साथ है। इस दौरान उत्तरी कमान के प्रमुख लैफ्टिनैंट जनरल रणबीर सिंह भी उनके साथ थे। रावत ने शहीद सैनिक के माता-पिता के साथ 30 मिनट बिताए। इससे पहले शहीद के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू-कश्मीर सरकार और सेना से राज्य से आतंकवाद खत्म करने तथा औरंगजेब की शहादत का बदला लेने की भावुक अपील की थी। इसी बीच शहीद के पिता मोहम्मद हनीफ का कहना था कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरे और भी बेटे हैं तथा मैं खुद भी देश के लिए कुर्बानी दूंगा।

आई.एस. का बड़ा दावा- श्रीनगर में ईद के दिन किया था सी.आर.पी.एफ. की बटालियन पर हमला

श्रीनगर । कुख्यात आतंकी संगठन आई.एस.आई.एस. ने श्रीनगर में सी.आर.पी.एफ. की बटालियन पर हुए एक हमले की जिम्मेदारी ली है। 16 जून को श्रीनगर के पंथा चौक पर सी.आर.पी.एफ. की 29वीं बटालियन और जम्मू-कश्मीर पुलिस पर हमला हुआ था। जम्मू-कश्मीर में हुआ यह तीसरा ऐसा हमला है, जिसकी जिम्मेदारी इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आई.एस.आई.एस. ने ली है। गत 16 जून को ईद की नमाज के बाद एक आतंकी ने दोपहर करीब सवा एक बजे पंथा चौक पर सी.आर.पी.एफ. की 29वीं बटालियन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। इस आतंकी हमले में सी.आर.पी.एफ. का एक जवान घायल हो गया था। इस हमले के दौरान पाकिस्तान और आई.एस.आई.एस. के झंडे भी फहराए गए थे। इससे पहले आई.एस.आई.एस. ने नवम्बर, 2017 में श्रीनगर के जाकुरा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में सब-इंस्पैक्टर इमरान टाक शहीद हो गए थे।

संपादकीय

कश्मीर के बिगड़ते हालाता

उन्होंने रमजान, रोजेदारों और ईद का भी ख्याल नहीं रखा और हमेशा की तरह मनमानी करते रहे। न जम्मू-कश्मीर शांत रहा और न लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी न आतंकवादियों ने भारत के इकतरफा संघर्ष विराम की भावना का सम्मान किया, न उनके आका पाकिस्तान और उसकी फौज ने। ईद खत्म होते-होते जब तमाम आलोचनाओं के बीच संघर्ष विराम के आगे बढ़ाने पर अटकलें लग रही थीं, इस जमात ने अपने खौफनाक इरादों पर बने रहने के कई संकेत ही दिए। सच तो यही है कि संघर्ष विराम का न उन्हें सम्मान करना था, न उन्होंने किया। सरकार ने रमजान शुरू होने के साथ ही इकतरफा युद्धविराम की घोषणा यह सोचकर की थी कि आतंक में लिपटी जमातें कुछ सीखेंगी और भविष्य के लिए कोई नई राह खुलेगी। यह एक ऐसा अवसर था, जिसका वे लाभ उठा सकते थे और कश्मीर में अमन की राह बना सकते थे। उन्होंने ऐसा तो नहीं ही किया, अमन के एक बड़े पैरोकार के रूप में चर्चित वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या कर दी। राइफल मैन औरंगजेब को अगवा करके मार डाला। अब जिस तरह लगातार पथराव की घटनाएं फिर सामने आई हैं और आतंवादियों के कई गिरोह के भारत में गुपचुप घुसने की खबर है, उसके बाद तो सरकार के पास संघर्ष विराम की दरियादिली छोड़, ऑपरेशन ऑल आउट में दोगुने जोश से जुटने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। जाहिर है, सरकार 28 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सतर्क है और किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। पिछले साल अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमले का सबक सामने है। आतंकवादी इस दौरान वारदातें पहले से ज्यादा तेज कर अपने मनसूबों का संकेत दे ही रहे हैं। ऐसे प्रयास या सौहार्द तभी कारगर होते हैं, जब सामने वाला सोचने की क्षमता रखता हो, लेकिन यहां तो न आतंकी जमातों के पास कुछ सोचने की क्षमता है, न उनके आकाओं के पास। कश्मीर के हालात एक बार फिर जैसी विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुके हैं, वह चिंता की बात है। कुछ-कुछ वैसा ही मंजर दिखने लगा है, जैसे हालात नब्बे के दशक में हो गए थे। तब जिस तरह आतंकवादियों के हौसले बुलंद थे, वे खुलेआम वारदात करते और धमकाते घूमते थे, कुछ वैसी ही भयावह अराजकता लौटती दिख रही है। ऐसे में, सदाशयता नहीं, सख्ती की ही जरूरत है। हम जम्मू-कश्मीर में पहले ही बहुत ज्यादा कुबार्नियां दे चुके हैं। अब और ज्यादा सदाशयता मांग के विपरीत होगी। बीते दिनों की घटनाओं के बाद एक बार फिर सख्त व निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही, ऐसा माहौल बनाने की दिशा में भी जुटने की आवश्यकता है, जो घाटी को स्थाई शांति दे सके। क्योंकि यह तो तय है कि गोली जैसे को तैसा दिखाकर किसी मुश्किल का तात्कालिक शमन तो कर सकती है, मगर समाधान नहीं दे सकती। समाधान का रास्ता तो विमर्श से गुजरता है। न उनके द्वारा की जा रही हत्याओं और पथराव में समाधान है, न किसी गोली या पैलेट गन में ही। हां, हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि पाकिस्तान इन मामलों को जिस तरह से हवा और मदद देता रहा है, कोई संदेह नहीं कि अपने आगामी आम चुनावों के मद्देनजर वह फिर कोई नया वितंडा खड़ा करा दे। आखिर वह पाकिस्तान है और किसी भी हद तक जा सकता है।

अब ऑपरेशन ऑलआऊट

केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध घोषित एकतरफा संघर्ष विराम को विवश होकर वापिस लेना पड़ा क्योंकि इसका सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। यह संघर्ष विराम रमजान के पाक महीने के दौरान घोषित किया गया था। सरकार के इस नरम रुख का जवाब आतंकवादियों ने हिंसा से दिया। संघर्ष विराम के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले होते रहे। एक स्थानीय पत्रकार और भारतीय सेना के जवान औरंगजेब को अगवा कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसका मतलब है कि आतंकवादियों ने सरकार के शांति प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अलबत्ता, कश्मीर घाटी में हाल फिलहाल अमन चैन की वापसी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। सच है कि घाटी में भाजपा का कोईजनाधार नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार भी वहां प्रभावहीन है। पिछले चुनाव के बाद घाटी में अपनी जमीन तैयार करने की रणनीति को सामने रखकर भाजपा पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन उसे अब तक कोईकामयाबी नहीं मिल पाई है। सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की लोकप्रियता भी तेजी से गिरती जा रही है, और उनका जनाधार भी खत्म हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सूबे में पूर्व अलगाववादी ताकतों के सहयोग से पीडीपी का राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था। अब महबूबा मुफ्ती भाजपा के सहयोग से सरकार चला रही हैं, लिहाजा अलगाववादी शक्तियां पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गई हैं। गौर करने वाली बात है कि महबूबा मुफ्ती दक्षिण कश्मीर से आती हैं, और इन दिनों आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र स्थल दक्षिण कश्मीर बना हुआ है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अलगाववादी-आतंकवादी ताकतों के मुख्य निशाने पर हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हद से ज्यादा खराब हो गएहैं। वहां की सेना और सरकार की ओर से अलगाववादियों को लगातार समर्थन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहना मुश्किल है कि कश्मीर में अमन-चैन कब कायम होगा। सरकार भी जानती है कि महज गोली और बंदूक से शांति कायम नहीं हो सकती, लेकिन आतंकवादियां के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के सिवाय सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

डूबती हिन्दमाता और..

हर साल लगभग हर साल खबर आती है, मुंबई में हिंदमाता पानी में। हर साल मुंबई में बारिश होती है। मुंबई का महानगर निगम आश्वासन देता है कि सब ठीक रहेगा, कुछ ना डूबेगा। पर हिंदमाता डूब जाती है। मेरी राय में अब वक्त आ गया कुछ आऊट ऑफ द बॉक्स थिंकिग का। हिंदमाता को डूबने से बचाना असंभव सा है। मुंबई में शिवसेना अपना पॉलिटिकल आधार बचा रही है, और भाजपा सुनिश्चित कर रही है कि शिवसेना का कुछ बच ना जाए। दोनों पार्टियां उस संस्था पर काबिज हैं, जिसका जिम्मा मुंबई को डूबने से बचाने का है। दोनों खुद को ही बचाने में इतनी बिजी रहती हैं कि हिंदमाता को कौन बचाए। तो कुछ नया सोचना चाहिए। हिंदमाता इलाके का नाम दाऊद इब्राहीम चौक किया जाए। हर साल डूबेगा इलाका तो खबर आएगी दाऊद डूबा। बहुत मार्मिक खबर आई-गांधी में आवारा कुत्तों ने बच्ची को नोचा। गांधी अस्पताल का नाम है, गांधी अस्पताल में नवजात बच्ची को आवारा कुत्ते नोच खसोट गए। गांधी के नाम पर यह नोच खसोट क्यों दर्ज हो। इस अस्पताल का नाम रख दिया जाना चाहिए कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज के नाम पर। ऐसे अस्पतालों के नाम ओसामा बिन लादेन के नाम पर रखे जाएं, हाफिज सईद हत्यारे के नाम पर रखे जाएं। महान आत्माएं शर्मिंदा तो ना हों। अस्पतालों के हालात बदलना मुश्किल काम है। नाम बदलना आसान। मेरे घर के करीब महाराणा प्रताप रोड पर चेन स्नैचरों का आतंक कई सालों से है। महाराणा प्रताप पर चेन स्नैचिंग खबर भी लगभग शाश्वत सी हो गई है। इस रोड का नाम ही बदल दिया जाना चाहिए। किसी कर्मठ और सफल चेन स्नैचर के नाम पर इसका नामकरण हो जाए तो चलने वालों को इसके खतरों का अंदाज हो जाए। आतंकी कसाब पर इसका नामकरण हो जाए तो महिलाएं धन्यवाद बोलें कि कसाब की सड़क पर तो जान भी जा सकती थी। पटेल रोड के लगभग सारे दुकानदार मिलावटिए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को मिलाकर रखा था, एक रखा था। उनके नाम पर बने रोड पर मिर्ची में लाल रंग मिलाया जा रहा है। इस रोड का नाम जनरल जिया उल हक रोड रख दिया जाए जिसने धर्म में आतंक की खतरनाक मिलावट कर दी थी पाकिस्तान में।

थर्ड अंपायर बनाम नवाज शरीफ

विभूति नारायण राय पूर्व आईपीएस अधिकारी

एक क्रिकेट-पागल समाज में स्वाभाविक ही है कि मैच फिक्सिंग शब्द राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन जाए। एक वक्त हॉकी और स्क्वैश जैसे खेलों के पावर हाउस पाकिस्तान के पास अब ले-देकर क्रिकेट ही बचा है- वह भी आधा-अधूरा। 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमले के बाद किसी भी महत्वपूर्ण क्रिकेट राष्ट्र ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और अपने घरेलू टेस्ट भी उसे दुबई जाकर खेलने पड़ते हैं। आईपीएल की तर्ज पर और ईर्ष्या में शुरू हुए पीएसएल के बमुश्किल दो-एक मैच पाकिस्तान में हो पाते हैं, शेष दुबई में खेले जाते हैं।

इन सबके बावजूद क्रिकेट को लेकर दीवानगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी शब्दावली मीडिया में छाई रहती है। दो महीने से भी कम समय बाकी है, जब पाकिस्तान में अगला चुनाव होना है और अजूबा ही सही, एक क्रम में लगातार तीसरी बार वहां चुनी हुई सरकार बनने जा रही है। ऐसे में, अगर टेलीविजन की बहसों या अखबारों में बार-बार मैच फिक्सिंग शब्द सुनाई या दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि एक क्रिकेटप्रेमी राष्ट्र अपनी बेबसी और झुंझलाहट का इजहार खेल की शब्दावली में कर रहा है। दिलचस्प है कि इस बार मैच फिक्सिंग पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े नायक इमरान खान के पक्ष में होने जा रही है।

पाकिस्तान की राजनीतिक बिसात पर शह और मात का फैसला अक्सर फौज की चाल से होता है। 2013 के आम चुनाव के एक साल के अंदर ही इमरान खान ने नवाज सरकार के खिलाफ जबर्दस्त आंदोलन छेड़ा था और छह महीने तक सरकार ठप्प सी रही। उस समय का एक विजुअल लोगों की स्मृति में टंका-सा है, जिसमें सेनाध्यक्ष से मिलकर लौट रहे इमरान अपने समर्थकों को दिलासा दे रहे हैं कि बस, तीसरे अंपायर की उंगली उठने ही वाली है। इशारा साफ था कि तीसरा अंपायर यानी फौज सरकार के खिलाफ निर्णायक हस्तक्षेप करने जा रही है। यह अलग बात है कि तत्कालीन घरेलू व वैश्विक परिस्थितियां ऐसी नही थीं कि सेना हाल में चुनी सरकार को बदल सके और उसे खामोश रह जाना पड़ा। पर इस पूरे घटनाक्रम का असर यह पड़ा कि अगले तीन वर्षों तक एक अपंग सरकार चली और चुनावी साल आते-आते मुस्लिम लीग (नून) को नवाज शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। इस बार फौज को साथ मिला है सुप्रीम कोर्ट का। परदे के पीछे दोनों के गठजोड़ ने ही वह परिस्थिति पैदा कर दी है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया मैच फिक्सिंग कह रहा है।

यह एक आम जानकारी है कि नवाज और इमरान, दोनों पाक सेना की निर्मिति हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे पारंपरिक राजनेता के मुकाबले तानाशाह जिया उल हक ने नवाज शरीफ को खड़ा किया और जब नवाज ने उड़ना शुरू किया, तो इमरान मैदान में उतारे गए। वह कई अर्थों में मुल्ला-मिलिट्री गठबंधन को मुफीद लगते हैं। विलायत में शिक्षा हासिल करने के कारण उनकी छवि एक आधुनिक मनुष्य की है, पर मदरसों से निकले तालिबान भी उन पर विश्वास करते हैं, फौज का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया और फिर क्रिकेट के पीछे दीवाने राष्ट्र को इस खेल का अकेला विश्व कप उन्हीं के नेतृत्व में तो मिला है। सब कुछ राष्ट्र-नायक बनाने के लिए आदर्श था, पर फौज की योजना के सामने रुकावट एक ऐसी बाधा बनी, जिसके बारे में उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। यह थी उनके चित्त की अस्थिरता। चाहे शादियों व तलाक के मसले हों या राजनीतिक फैसलों के, इमरान की अपरिपक्व जल्दबाजी और निर्णयों को पलटने की उनकी आदत ने अक्सर उन्हें हास्यास्पद ही बनाया है।

नवाज शरीफ को हटा तो दिया गया, पर जिस तरह उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ी है, उसने साफ कर दिया कि उन्हें हरा पाना मुश्किल होगा। इससे मैच को फिक्स करने में सेना व न्यायपालिका को ओवर टाइम खेलना पड़ रहा है। उन्हें पद से अयोग्य घोषित करना और उन्हीं की तरह के आरोपों पर इमरान को बरी करना ही काफी नहीं था, जरूरी था कि उन्हें जेल भेजकर सत्ता की दौड़ से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। इसके लिए चीफ जस्टिस ने न्यायिक मर्यादाओं की सारी हदें पार करते हुए नवाज के खिलाफ अदालतों में मुकदमे कायम कराए और स्वयं उनका पर्यवेक्षण शुरू कर दिया। पूरी कोशिश है कि चुनावों के नतीजे आने से पहले ही नवाज को सजा सुना दी जाए। पूर्व फौजी तानाशाह परवेज मुशर्रफ को अदालत की पेशी से बच निकलने में मदद करने वाली सेना और सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को लंदन के अस्पताल में मृत्यु शय्या पर पड़ी अपनी पत्नी को देखने जाने की छूट देने को भी तैयार नहीं हैं। ट्रायल कोर्ट को चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि छुट्टियों में भी सुनवाई हो और ईद के मौके पर नवाज की लंदन यात्रा पर रोक लगाने की असफल कोशिश की गई। मकसद साफ है, किसी तरह आम चुनाव के पहले नवाज को सजा सुनाना।

यदि आप इन दिनों पाकिस्तानी चैनलों पर चल रही बहसों को सुनें, तो आपका ध्यान उस साफगोई पर गए बिना नहीं रहेगा, जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसर यह विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि नवाज की सजा बस कुछ दिनों की बात है। प्रिंट में भी इसी तरह की भविष्यवाणियां भरी पड़ी हैं। एक माहौल बन रहा है कि इमरान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सत्ता में आ रही है। अब तक हुआ भी यही है कि अमूमन वही जीतता है, जिसे फौज चाहती है। नतीजतन, राजनीतिक हलकों में भगदड़ सी मची है। हर पार्टी का ढुलमुल यकीन इमरान की पार्टी में भागा चला जा रहा है।

अभी नहीं कहा जा सकता कि इस मैच फिक्सिंग का क्या नतीजा होगा, पर अगर इमरान जीते, तो फौज ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगी, भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार की संभावनाएं धूमिल होंगी और मजहबी कट्टरपंथियों को खाद मिलेगी। नवाज की सहानुभूति में जन-उभार को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि नब्बे के दशक में इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद बनाकर बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने में असमर्थ सेना शायद इस बार भी जनता का फैसला बदलवा न पाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

> "इमरान खान के पक्ष में चुनीवू नतीजा आए, इसके लिए पाकिस्तानी सेना और न्यायपालिका को ओवर टाइम खेलना पड़ रहा है।"

ग्राम न्यायालय योजना

उदासीनता के चलते लक्ष्य अधूरे

अनूप भटनागर

देश की निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या घटाने के इरादे से सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं। इसके अंतर्गत लोक अदालत, त्वरित अदालत, सांध्य अदालत और ग्राम अदालत जैसे कई प्रयोग किये गये। सरकार ने ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर ही न्याय सुलभ कराने के इरादे से नौ साल पहले ग्राम न्यायालय कानून, 2009 लागू किया था। इस कानून के तहत पांच हजार से अधिक ग्राम अदालतों की स्थापना की कल्पना की गयी थी लेकिन इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

ऐसा लगता है कि न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के प्रति उदासीनता की तरह ही ग्राम न्यायालय स्थापित करने में भी राज्यों की दिलचस्पी नहीं है। देश के 29 राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों में से अभी तक सिर्फ 11 राज्यों में केवल 343 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया जाना है लेकिन इनमें से भी सिर्फ नौ राज्यों में 210 ग्राम न्यायालय ही काम कर रहे हैं।

नौ साल पहले महात्मा गांधी के जन्म दिन पर लागू की गयी ग्राम न्यायालय योजना राज्यों की उदासीनता और केन्द्र सरकार से अपेक्षित वित्तीय सहायता के अभाव में सिसकियां भर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विवादों को गांव की सीमा में सुलझाने का यह प्रयास भले ही सराहनीय हो लेकिन इसके लिये केन्द्र से आर्थिक मदद मिलने के बावजूद राज्य सरकारों का इनके प्रति उदासीन रवैया लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के प्रति उनकी नीयत को ही दर्शाता है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के एक पत्र के अनुसार ग्राम न्यायालय स्थापित करने और उनके परिचालन की योजना 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 31 मार्च, 2020 तक जारी रहेगी। इस पत्र में स्पष्ट किया गया था कि इस योजना हेतु दिसंबर, 2009 के केन्द्रीय सहायता संबंधी सामान्य दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार ने ग्राम न्यायालय स्थापित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रति ग्राम न्यायालय 18 लाख रुपए, कार्यालय भवन हेतु दस लाख रुपए, वाहन हेतु पांच लाख रुपए और कार्यालय की साज-सज्जा हेतु तीन लाख रुपए प्रदान करने की योजना बनाई थी। इस कानून का उद्देश्य नागरिकों को उनके घर तक न्याय पहुंचाने के लिये ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना था।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 89, राजस्थान में 45, ओडिशा में 14, महाराष्ट्र में 24, पंजाब के 22 जिलों में एक तथा हरियाणा के 21 जिलों में दो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 104 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया था लेकिन इनमें से केवल चार और केरल में 30 ग्राम न्यायालय ही कार्यरत हैं। महाराष्ट्र में इन ग्राम न्यायालयों ने 12423 मामलों का निपटारा किया जबकि केरल ने इनमें 25018 मामलों का निपटारा किया है। जहां तक इस योजना के लिये वित्तीय सहायता का सवाल है तो केन्द्र के 2017-18 के बजट के दौरान आठ करोड़ रुपए सहित अब 52.60 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं लेकिन इस योजना के अंतर्गत धीमी प्रगति हो रही है।

इस स्थिति के मद्देनजर संसदीय समिति ने ग्राम न्यायालय योजना को अधिक प्रभावकारी बनाने पर जोर देते हुए इनके लिये ज्यादा केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है। समिति महसूस करती है कि यद्यपि ग्राम न्यायालयों ने वादों के त्वरित निपटारे अथवा गरीबों के लिये इसे कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं की है लेकिन ठोस, सुनियोजित तथा निरंतर प्रयास करके इसे हासिल किया जा सकता है।

समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि केन्द्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों से नियमित रूप से अपने यहां ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध करती रही है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से ग्राम न्यायालय योजना के अंतर्गत ग्राम न्यायालय की स्थापना करने और उनके संचालन के लिये वित्तीय सहायता मांगने का भी अनुरोध किया है। ग्राम न्यायालयों की धीमी प्रगति के कारणों पर अप्रैल 2012 में विधि एवं गृह सचिवों तथा उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल की बैठक में चर्चा के दौरान सामने आया एक कारण तो अपेक्षित वित्तीय सहायता नहीं मिलना भी रहा। इसके अलावा अन्य कारणों में ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने में पुलिस अधिकारियों तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की अनिच्छा, नोटरी और स्टाम्प विक्रेताओं की अनुपलब्धता और इससे भी अधिक नियमित अदालतों के समान अधिकारी क्षेत्र की समस्या भी सामने रखी थी।

उम्मीद की जानी चाहिए कि कर्ज और सूदखोरों के जंजाल में फंसे किसानों, खेतीबाड़ी और ऐसे ही अन्य विवादों के गांव में ही समाधान के लिये राज्य सरकारें अधिक गंभीरता से नये ग्राम न्यायालयों की स्थापना करेंगी।

पाकिस्तान

मुद्दे जो हावी रहेंगे

कुलदीप तलवार

पाकिस्तान में आम चुनाव 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। संसद व चारों प्रांतों की असेंबलियों के चुनाव उसी दिन होंगे। मतदाताओं की संख्या दस करोड़ पचास लाख है। 4 करोड़ साठ लाख युवा मतदाता हैं। क्रि केट से नेता बने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज पार्टी और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन्स के बीच त्रिपक्षीय मुकाबला होगा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा पाक की दिन-ब-दिन खराब होती अर्थव्यवस्था है। बेरोजगारी चरम पर है। प्रांतों के साथ मतभेदी व्यवहार भी एक बड़ा मुद्दा है। देश में पंजाब प्रांत का दबदबा है। पंजाब को बांटकर सरायकी और भावहलपुर प्रांत बनाने की मांग जारी है। इमरान खान खुद को नवाज शरीफ के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। शरीफ अदालत द्वारा अयोग्य ठहराए जाने से खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। इमरान अपनी पार्टी में अपराधियों, इस्लामिक चरमपंथियों, बलात्कारियों और डाकुओं की मौजूदगी से मुश्किल में हैं। उनके चरित्र पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। अपनी तीन पत्नियों को तलाक दे चुके हैं। उनकी पत्नी रेहम खान की किताब ''टेलऑल' के लीक हुए कुछ अंशों ने तहलका मचा रखा है। ये अंश इमरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेहम खान ने कहा है कि उनकी किताब खुलासा करेगी कि कैसे राजनीतिक पदों के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कैसे सैक्सुअल फेवर होता है। रेहम खान ने यह भी कहा है कि इमरान इस धरती पर सबसे गंदा इंसान है। कुछ अरसे से पाकिस्तान में ''पख्तून तहफ्फुज आंदोलन' चल रहा है। राजनेता इसका विरोध नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसा किया तो पख्तूनों का वोट नहीं मिल पाएगा। पख्तून राष्ट्रवादी पाक सेना और आईएसआई से इसलिए नाराज हैं कि सेना द्वारा कबाईली क्षेत्र में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के खात्मे के लिए बमबारी में उनके हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी। उनके घर तबाह हो गए। आईएसआई द्वारा हजारों पख्तूनों को अगवा कर लिया गया जिनका अभी तक पता नहीं लग सका कि जिंदा हैं, या मार दिए गएहैं। पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि पख्तून देश विरोधी भावनाएं उकसा रहे हैं। देश की लगभग 20 प्रतिशत आबादी पख्तून है। इसलिए चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आसिफ अली जरदारी की पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। उनके पुत्र बिलावल भुट्टो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बिलावल को खुद को साबित करने का शायद अन्तिम अवसर साबित हो सकता है। नवाज शरीफ इन दिनों फौज, आईएसआई के घेरे में फंसे हुए हैं। मुख्य कारण है उनका वह बयान जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान से जाकर आंतकवादियों ने 2008 में मुंबई में 150 निदरेष लोगों की जान ले ली और उनका यह पूछना कि आखिर, उनके खिलाफ ट्रायल क्यों नहीं पूरा करते। उनके बयान से मुंबई हमले के पीछे पाक फौज की साजिश का पता चलता है। पाक अदालत दहशतगर्दी के लिए कवच का काम करती रहती है। नवाज शरीफ के समर्थक इस बात को सोशल मीडिया पर बराबर कह रहे हैं कि पाक सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को सेना ने नवाज शरीफ और उनके परिवार को बर्बाद करने के लिए कहा है। सेना चाहती है कि अदालत नवाज शरीफ को दंडित करे और जेल में डाल दे लेकिन चुनाव में इसका उल्टा असर भी हो सकता है। लोग नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ के समर्थन में आगे आ रहे हैं। समझने लगे हैं कि अदालत ने शरीफ को पार्टी के मुखिया और प्रधानमंत्री के पद से सेना के इशारे पर हटाया है। चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है ताकि शरीफ राजनीति से ताउम्र के लिए बाहर हो जाएं।मुंबई हमले की साजिश करने वाले आतंकवादी हाफिज सईद की पार्टी जमात-उल-दावा निष्क्रिय पड़ी पार्टी ''अल्ला-हू-अकबर' के जरिए चुनाव में शामिल हो रही है। लेकिन पाक के लोग कट्टरपंथी पार्टियों की माली मदद तो करते हैं लेकिन वोट नहीं देते क्योंकि वो समझते हैं कि कट्टरपंथी पार्टियां देश और समाज का पैमाना नहीं बन सकतीं। माना जा रहा है कि पाक सेना सब पर भारी है। इसलिए चुनाव में जीत पाक सेना और आईएसआई के दबाव पर तय होगी। बहरहाल, चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि इस बार सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले युवा सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मतदाता, जिनमें युवा मतदाता ज्यादा हैं, न सिर्फ ऑनलाइन प्रचार के उपकरणों का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि चुनाव के दिन बड़ी संख्या में मताधिकार का इस्तेमाल कर चुनावी तस्वीर को भी बदल सकते हैं।

तेज प्रताप का पूर्व सचिव बताकर लगाया आरोपः लालू परिवार को दीमक की तरह खा रहे ये लोग

एजेंसी, पटना

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने हाल ही में पार्टी में कुछ चुगलखारों की चर्चा करते हुए अपनी अनदेखी का आरोप लगाया था। उन्होंने पार्टी में असामजिक तत्वों के जमावड़ा की भी बात कहकर सनसनी फैला दी थी। पार्टी के वरिष्ठों के हस्तक्षेप से लालू परिवार में वर्चस्व का विवाद सुलझा तो लिया गया, लेकिन तेज प्रताप के कथित पूर्व सचिव ने पार्टी के ऐसे तत्वों का खुलासा करता बयान देकर फिर विवाद खड़ा कर दिया है। खुद को तेज प्रताप यादव का पूर्व सचिव बताने वाले अभिनन्दन यादव ने कहा है कि पार्टी के तीन फ्रॉड लोग नहीं चाहते कि तेज प्रताप नेता बनें। अभिन्दन ने कहा कि पार्टी के मणि यादव, ओमप्रकाश यादव तथा नागमणि यादव ही तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिश करते हैं। वे पार्टी व लालू परिवार को दीमक की तरह खा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि तीनों लोग महा फ्रॉड हैं और वे मैडम (राबड़ी देवी) की गलत कान भरते रहते हैं। उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभिनन्दन ने कहा कि वे आठ साल तक तेज प्रताप के पीए रहे। बीच में इन तीनों के कारण ही उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन, अब वे फिर तेज प्रताप के साथ हैं। मणि यादव, ओमप्रकाश यादव तथा नागमणि यादव सगे भाई हैं। वे राबड़ी देवी के रिश्ते के भाई के बेटे हैं तथा उन्हें बुआ बोलते हैं। मणि यादव, तेजस्वी के

ओमप्रकाश, तेज प्रताप के और नागमणि राबड़ी के निजी सचिव हैं। अभिनंदन यादव के बयान का खंडन करते हुए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बताया कि वह कभी पार्टी में नहीं रहा। राजद से जुड़े कुछ अन्य लोगों के अनुसार अभिनंदन यादव कभी भी तेज प्रताप यादव का निजी सचिव नहीं रहा। तेज प्रताप के विधायक बनने से पहले उदय यादव उनके निजी सचिव थे। बाद में मंत्री बनने पर ओम प्रकाश भी तेज प्रताप यादव से जुड़ गए। बताया जा रहा है कि खुद को पूर्व निजी सहचव बताने वाला अभिनंदन, लालू यादव का रिश्तेदार भी नहीं है। वह दानापुर का रहने वाला है। तेज प्रताप के बयान के बाद के बाद सुलझते दिख रहे इस मामले को इस बयान ने फिर विवादित कर दिया है। इस बाबत आरोपों के घेरे में आए तीनों की प्रतिक्रिया अभी नहीं मिल सकी है। हालांकि, राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि अभिनंदन यादव का राजद से कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसकी बातें निराधार हैं। राजद ने अभिनन्दन के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन तेज प्रताप के तेवर के बाद अब इस बयान से फिर नए विवाद की आशंका है। पार्टी अभी नाजुक और पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है।

आसमान से बरस रहा आग, इंसान के साथ पशु पक्षी भी बेहाल

एजेंसी, मुजफ्फरपुर

बगहा,मानसून में देरी की वजह से बीते कई दिनों से आसमान से बरस रही आग ने मनुष्यों समेत पशु-पक्षियों तक का जीना दुश्वार कर दिया है। आलम यह है कि सुबह में दिन चढ़ने से पहले ही दोपहर में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगता है और सुबह 10 बजे से ही हरनाटांड़ सहित क्षेत्र की सड़कों पर भी सन्नाटा पसर जाता है। वहीं सप्ताह भर से तापमान का पारा, जो 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था, बीते चार पांच दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस की ऊंचाई छूने लगा है। मौसम जानकारों की माने तो अगले सप्ताह भर में भी थरुहट वासियों को इस प्रचंड गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं दिख रहे है। मौसम में जरा सी लापरवाही मनुष्यों से लेकर पशु पक्षियों तक के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस दौरान लू की चपेट में आए किसी भी प्राणी की ससमय इलाज नहीं होने पर मौत भी हो सकती है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। चिकित्सक ऐसे मौसम में खाने पीने में एहतियात बरतने के साथ धूप से भी बचाव की सलाह दे रहे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए तेज धूप से बचें हरनाटांड़ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. कृष्णमोहन राय बताते हैं कि क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लोगों के बीच डी हाईड्रेशन, लू, डायरिया, वोमेटिंग, आंखों में जलन एवं चर्म रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

शॉर्ट न्यूज

राजद का पोस्टरः अर्जुन बने तेजस्वी के निशाने पर मोदी-नीतीश, तेजप्रताप बने सारथी

पटना। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। राजनीति के इस महाभारत के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का एक पोस्टर सामने आया है। पटना स्थित राजद कार्यालय के पास लगाए गए इस पोस्टर में अर्जुन बने तेजस्वी के सारथी की भूमिका में कृष्ण बने तेजप्रताप हैं। तेजस्वी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हैं। पोस्टर में अपने तीर से पीएम मोदी, सीएम नीतीश तथा अमित शाह पर निशाना लगाते तेजस्वी के सारथी तेज प्रताप के पीछे सामाजिक न्याय के दो बड़े चहरे बाबा साहेब अंबेडकर तथा कर्पूरी ठाकुर के चेहरे नजर आ रहे हैं। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव राजा की भूमिका में दिख रहे हैं। साथ में राबड़ी देवी व मीसा भारती भी हैं। राजद के इस पोस्टर में संविधान बचाओ यात्रा तथा आरक्षण बचाओ आदि नारे भी लिखे हैं। पोस्टर राजद में तेजस्वी व तेजप्रताप की भूमिका को स्प्ष्ट करता है। तीन के निशाने पर रखे गए पीएम मोदी, नीतीश कुमार व अमित शाह की तस्वीरों तथा दर्ज नारों से राजद के फ्यूचर प्लान का खाका भी स्पष्ट हो जाता है।

किशनगंज में धर्मस्थल में तोड़फोड़ से तनाव, सड़क जाम कर आगजनी

किशनगंज। बिहार के किशनगंज में एक धर्मस्थल में असामाजिक तत्वों की तोड़फोड़ के कारण तनाव है। घटना से भड़के समुदाय विशेष के लोग सड़कों पर उतर गए। जानकारी के अनुसार किशनगंज के खगड़ा स्थित हलीम चौक पर सोमवार की देर रात एक धर्मस्थल में घुसकर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। उन्होंने धर्मस्थल के भीतर प्रतिमा को तोड़ दिया। घटना की जानकारी लोगों को सुबह में हुई। मंगलवार की सुबह जब लोग धर्मस्थल गए तो वहां हुई घटना का पता चला। इसके बाद यह बात पूरे इलाके में फैल गई। घटनास्थल पर एक समुदाय के सैकड़ों लोग जुट गए। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ के विरोध में एनएच 31 को जाम कर दिया। उन्होंने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी भी की। स्थिति अभी तक तनावपूर्ण बनी हुई है।

उफनाई गंडक तो फिर मचाएगी तबाही, दहशत में लोग

मुजफ्फरपुर। बूढ़ी गंडक उफनाई तो क्षेत्र में इस बार भी 20 पंचायतों में बाढ़ तबाही मचाएगी। कारण बनेगी विभाग की उदासीनता और लापरवाही। समय रहते तटबंधों की सही तरीके से मरम्मत भी नहीं कराई जा सकी है और ऐसा ही हाल स्लूस गेटों का भी है। इससे विगत वर्ष की बाढ़ की तबाही झेल चुके लोग इस बार भी सशंकित हैं। उनका कहना है कि इस बार भी बाढ़ जरूर आएगी। जल संसाधन विभाग की नींद साल मे एक या दो बार टूटती है। समय रहते अधिकारी नहीं चेतते हैं। वहीं जब बाढ़ दस्तक देती है तो सक्रिय हो जाते हैं। उस समय किसी तरह लोगों की जान बचाना जरूरी रहता है। रेन कट से लेकर अन्य कटाव व बचावरोधी काम शुरू होता है। तटबंध की वर्तमान स्थिति काफी खराब है। सिकन्दरपुर से लेकर कोठियां, राजबाड़ा, बुधनगरा, डुमरी, बिंदा, नरौली, सलहा, बैकटपुर, दरधा तक दो दर्जन से अधिक जगहों पर इसकी स्थिति काफी खराब है। अभी तक रेन कट को नहीं भरा जा सका है। वहीं कुछ जगह स्लूस गेटो की मरम्मत का काम चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है।

माओवादियों ने की गला रेतकर एक की हत्या

जमुई। बिहार-झारखंड सीमा के पंचरूखी मोड़ के समीप हथियारबंद माओवादियों ने सोमवार की देर रात गला रेतकर एक युवक की हत्या कर दी। युवक की लाश बेलवाघाटी से मधुपुर जाने वाली रास्ते पर पंचरुखी मोड़ के समीप बरामद किया गया। लाश के समीप लगभग एक दर्जन पर्चा बरामद किया गया। पर्चा में युवक पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। बेलवाघाटी थाना का विनोद कुमार बर्णवाल जूता व खैनी का फेरी का काम करता था। सोमवार की सुबह 10 बजे वह फेरी के काम से चकाई थाना के मड़वा और गोस्वारा गांव गया था। शाम में लौटने के क्रम में हथियारबंद तीन सौ की संख्या में माओवादियों ने मंझलाडीह गांव के समीप उसका अपहरण कर लिया। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने काफी खोजबीन की परंतु उसका पता नहीं चला। माओवादियों ने देर रात जन अदालत लगाकर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। सुबह ग्रामीणों ने परिजन को सूचना दी कि एक युवक की सिर कटी लाश पंचरुखी मोड़ के समीप पड़ी है।

कटिहार में चोरी की 25 बाइकें बरामद, तीन धराए

कटिहार। कोढ़ा पुलिस ने रविवार रात को जुराबगंज गांव में छापेमारी कर चोरी की दो दर्जन बाइकें बरामद करने के साथ तीन आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस इन्हें अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य मान रही है। बरामद बाइकों में से कुछ के दूसरे राज्यों से चोरी होने की बात कही जा रही है। पुलिस इनके नंबरों की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जुराबगंज के शातिरों द्वारा दूसरे राज्यों-जिलों से बाइक चोरी करने की सूचना मिलने पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया था। सदर एसडीपीओ अनिल कुमार के नेतृत्व में की गई छापामारी में 25 बाइकों के साथ तीन आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान नौ पल्सर, पांच पैशन प्रो, दो शाइन, तीन अपाचे व एक केटीएम बाइक के अलावा पांच स्कूटियां भी बरामद की गई। इस दौरान सुरेश यादव, सिकंदर यादव व अमित यादव को भी गिरफ्तार किया गया।

नवरुणा हत्याकांड में चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

एजेंसी, मुजफ्फरपुर

नवरुणा हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद चार आरोपितों की जमानत की अपील अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ तिवारी ने खारिज कर दी है। ये आरोपित हैं बिल्डर व प्रॉपर्टी डीलर ब्रजेश सिंह, निजी हॉस्पीटल के प्रोपराइटर विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला, होटल व्यवसायी अभय गुप्ता और मार्बल व्यवसायी विमल अग्रवाल। इनकी जमानत की अर्जी पर पहले ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी। इसे कोर्ट ने आदेश पर रखा था। सभी अर्जी पर एक साथ कोर्ट का आदेश आया है। सीबीआइ कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है जमानत: 29 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आधा दर्जन आरोपितों ने सीबीआइ कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अर्जी खारिज होने पर इनमें से इन चार आरोपितों ने जिला जज के यहां अपील की थी।

यह है मामला : 18 सितंबर 2012 की रात नगर थाना के जवाहरलाल रोड स्थित अपने आवास में सोई अवस्था में नवरुणा का अपहरण कर लिया गया था। ढाई माह बाद सफाई के दौरान उसके घर के निकट के नाले से मानव कंकाल बरामद हुआ था। डीएनए टेस्ट के बाद यह कंकाल नवरुणा का साबित हुआ।

इस मामले की जांच पुलिस के बाद सीआइडी ने की। नतीजा नहीं निकलने पर फरवरी 2014 से इसकी जांच सीबीआइ कर रही है। पिछले साल चार सितंबर को नगर निगम के वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा को संदिग्ध आरोपित बताते हुए सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारण उन्हें जमानत मिल गई थी। इस साल 28 अप्रैल को सीबीआइ ने छह संदिग्ध आरोपितों को गिरफ्तार किया। ये सभी 20 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

बीजेपी ने कहा- सभी सीटिंग सीट पर उतारेंगे उम्मीदवार, जेडीयू ने कहा- अकेले लड़िए ना फिर...

एजेंसी, पटना

बिहार एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा है कि पार्टी बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। बीजेपी गठबंधन पार्टियों से मिलकर सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़कर लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां से पार्टी के वर्तमान में सांसद हैं और चुनाव जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। सासाराम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गठबंधन के सभी दलों को उसका हक दिया जाएगा, लेकिन उन सीटों पर जहां बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, उस पर बीजेपी फिर से अपना कैंडिडेट उतारेगी। बता दें कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं

और फिलहाल बीजेपी के 23, लोजपा के 6 रोलसपा के 3 और जदयू के दो सांसद हैं। इस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जदयू ने तंज कसा है और पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि ऐसे में तो भाजपा को सहयोगियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अकेले ही सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और जीत सकती है। संजय सिंह ने कहा कि जो कोई ऐसी बयानबाजी करता है तो उसे ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। बिहार में एनडीए के बड़े भाई नीतीश कुमार जी हैं और वही सबसे बड़ा चेहरा हैं। उनके अलावा बिहार में कोई है ही नहीं, इसीलिए सभी दल नीतीश कुमार जी का ही चेहरा चाहते हैं चुनाव के लिए।

सीएम ने चांदन डैम का लिया जायजा, अभियंताओं का दिया निर्देश

बांका। सीएम ने दिया चांदन डैम को किसानों के लिए लाभकारी बनाने का निर्देश मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका पहुंचे। उन्होंने चादन डैम स्थित कार्यक्रम स्थल पर जाकर डैम का जायजा लिया और अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए। सीएम द्वारा डैम पर पौधरोपण करने के बाद अभियंताओं ने उन्हें डैम में गाद भरने के कारण गर्मी में डैम में पानी नहीं रहने की जानकारी दी। सीएम ने सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता से इस समस्या के समाधान के बारे में चर्चा की। उन्होंने डैम को किसानों के लिए लाभकारी बनाने पर बल दिया। सीएम यहां के बाद सिंचाई विभाग के आईबी जाएंगे। वहां वे बांका जिले के विकास का प्रजेंटेशन देखेंगे।

सावधान! बिहार में ठीक नहीं मॉनसून की नीयत, 19 जिलों में सूखे की आशंका

एजेंसी, पटना

मौसम का मिजाज बता रहा है कि इस बार बिहार में मॉनसून की नीयत ठीक नहीं है। जून के पहले सप्ताह में होने वाली प्री मॉनसून बारिश ने भी किसानों को चिंतित ही किया है। कृषि विभाग के मुताबिक 18 जून तक अनुमानित आंकड़ों से 23 फीसद कम बारिश हुई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 13 फीसद था। पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक आधी बारिश हो सकी है। इसका सीधा असर धान के बिचड़े पर पड़ रहा है। अभी तक के हालात बता रहे हैं कि राज्य के 19 जिले सूखे की ओर अग्रसर हैं। इन जिलों में जून में अभी तक 50 फीसद से भी कम बारिश हुई है। इससे किसानों को भारी परेशानी हो

रही है। खरीफ के बिचड़े पर सूखे का असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में किसान धान के बिचड़े की बुआई भी नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने की है, उनके खेत सूख गए हैं। हालांकि, कुछ जिलों में अच्छी प्री मॉनसून बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने बिहार में मॉनसून के प्रवेश का अनुमान जून के दूसरे सप्ताह में 10 से 12 जून के बीच किया था, किंतु छह दिन बाद भी इसका अता-पता नहीं है। उल्टे गर्म हवाएं एवं लू चल रही हैं। ऐसे में स्थानीय कारणों से भी बारिश के आसार बहुत कम रह गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों ही स्थितियों से मुकाबले की तैयारी कर रही है।

मुंगेर के खिलाड़ियों के बिना पूरी नहीं होती है बिहार फुटबाल टीम

मुंगेर। देश में क्रिकेट को लेकर दिवानगी ने कई खेलों को नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद मुंगेर में फुटबाल खेल के प्रति लोगों का जुनून सर चढ़ कर बोलता है। यही कारण है कि जिला मुख्यालय के पोलो मैदान से लेकर गांव के मैदान तक सुबह शाम युवा फुटबाल खेलते दिख जाते हैं। अब मुंगेर में युवा मेसी, रोनाल्डो आदि के बारे में चर्चा करते दिख जाते हैं। जिला फुटबाल एसोसिएशन के सचिव सह बिहार फुटबाल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रवींद्र सिंह ने कहा कि फुटबाल खेल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयास नहीं किए जाते हैं। अभी तक बेहतर स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है। इसके बावजूद मुंगेर राज्य में सबसे अधिक जूनियर खिलाड़ी पैदा करने वाला जिला है।

2.69 करोड़ से शवदाह गृह के जीर्णोद्धार का काम शुरू

एजेंसी, भागलपुर

बरारी में डेढ़ दशक से बंद पड़े शवदाह गृह के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया। जर्जर भवन को दुरुस्त में 2.69 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर विकास विभाग के आदेश पर भागलपुर नगर निगम ने बिहार राज्य जल पर्षद को पहली किश्त के रूप में 1.34 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दी है। शवदाह गृह भवन के जीर्णोद्धार का कार्य का जायजा लेने के लिए सोमवार को मेयर सीमा साहा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा पार्षदों के साथ पहुंचे। यहां निर्माण कार्य को गति देने के लिए जल पर्षद के अभियंता को निर्धारित अवधि तक कार्य पूरा करने को कहा है। अभियंता ने समय पर कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। मेयर ने कहा कि वर्षो से बंद पड़े विद्युत चालित शवदाह गृह शुरू होने से पांच जिलों के लोगों को सुविधा मिलेगी। इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। नगर निगम द्वारा यहां संसाधन भी विकसित किए जाएंगे। श्मशान घाट में मनमानी से राहत मिलेगी।

नगर निगम ने इसके लिए नीति का निर्धारण कर ली है। जलावन, शव जलाने, और सुविधा शुल्क का रेट तय किया जाएगा। शवदाह गृह परिसर में नगर निगम द्वारा एक हॉल बनाया जाएगा। इसमें निगम का काउंटर रहेगा। जिसमें सभी तरह के शुल्क एक साथ जमा होगा। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र का निबंधन भी काउंटर पर होगा। इस मौके पर वार्ड पार्षद खुशबू देवी भी मौजूद थी।

अमेरिका और जर्मनी सहित यूरोपीय | **शहद के उत्पादन से जिले में तकरीबन 50 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है**

अमेरिका और जर्मनी में मिठास घोल रही मुजफ्फरपुर के शाही लीची की शहद

एजेंसी, मुजफ्फरपुर

शाही लीची की तरह सबको चाहिए बिहार के मुजफ्फरपुर की शहद। हल्के सुनहरे रंग व विशेष खुशबू वाली शहद की खपत अमेरिका और जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों में बढ़ गई है। जिसने भी एक बार शहद का स्वाद चखा, दीवाना हो गया। शहद के उत्पादन से जिले में तकरीबन 50 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। कारोबार बढ़ा तो बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई और देखते ही देखते 300 करोड़ रुपये का व्यवसाय हो गया। जिले में करीब 50 हजार मधुमक्खी पालक शहद उत्पादन से जुड़े हैं। लीची से शहद निकालने का समय बमुश्किल 15 से 20 दिन का होता है। इतने ही दिनों में दो बार शहद निकल जाता है। उत्पादन चार से पांच हजार टन होता है। मुख्य रूप से मार्च

माह में ही लीची से शहद का उत्पादन मधुमक्खी पालक करते हैं। इसके उपरांत सरसों, यूकेलिप्टस, बाजरा और तिल आदि से शहद निकालने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में चले जाते हैं। इस काम में जुटे मोहन कुमार, शंभू प्रसाद व राजेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि दूसरे राज्यों में निर्धारित समय के लिए खेत मालिकों से जमीन किराए पर ली जाती है। यहां मधुमक्खी पालक अपने बक्से के साथ पहुंचते हैं।

आम की लकड़ी का 10 खाने का बक्सा तैयार किया जाता है। एक रानी व हजारों कामगार मधुमक्खियां इसमें रखी जाती हैं। जिस पौधे या पेड़ से शहद निकालना होता है, बक्सा उसके आसपास रखा जाता है। इन 10 खानों में ही मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं। रानी मधुमक्खी इनमें से कई छत्तों में अंडे देती है। कामगार मधुमक्खियां दूसरे छत्ते में शहद जमा करती हैं। फूलों में पराग के हिसाब से 10 या 15 दिनों में शहद छत्ते में भर जाता है। इसे निकाल लिया जाता है। तब, अंडा वाले छत्ते से कामगार मधुमक्खियां निकल आतीं हैं और फिर शहद निर्माण में जुट जातीं हैं। एक बक्से में 40 से 50 हजार कामगार मधुमक्खियां होती हैं। यहां उत्पादित शहद में से 90 फीसद बाहर चला जाता है। औसतन 40 हजार टन शहद का उत्पादन मधुमक्खी पालक सालाना करते हैं। इनकी मेहनत का ही असर है कि बिहार आज शहद उत्पादन में अग्रणी है। कारोबार तीन सौ करोड़ तक पहुंच गया है। आधा दर्जन कंपनियां यहां से शहद खरीदकर देश-विदेश के बाजार में भेजती हैं। शहद उत्पादन व कारोबार से जुड़े दिलीप शाही कहते हैं, पश्चिमी देशों में चीनी का इस्तेमाल कम होता है। वे लीची के शहद का अधिक सेवन करते हैं। यह जल्द जमता नहीं और वसा की मात्रा भी नहीं होती। वजन घटाने में भी कारगर है। इसकी कीमत अन्य शहद से अधिक होती है। बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार बताते हैं कि राज्य सरकार के कृषि रोडमैप में मधुमक्खी पालन को शामिल किया गया है। मधुमक्खी पालकों को अनुदान के साथ प्रोत्साहन व प्रशिक्षण की योजना बनी है। सरकार ने इसके लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया है। इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।

गांधीआश्रम से भारत-पाकिस्तान शांति एकता यात्रा निकली थी जिसमें जिग्नेश मेवाणी भी उपस्थित हुए।

अमरेली में पंजा ने कमल को कुचल कर रख दिया

धानाणी के गढ में सभी ११ तहसील पंचायत में कब्जा

अहमदाबाद। विपक्षी पार्टी के नेता परेश धानाणी के लिए आज काफी बड़ा और खुशी का समाचार आया था कि, पाटीदारों के गढ माना जाता अमरेली जिले की सभी ११ तहसील पंचायत पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है। अमरेली में कांग्रेस के पंजा ने भाजपा के कमल को कुचल दिया गया था और सभी सीट पर विजय लेते हुए कांग्रेस की छावणी में भारी उत्साह, खुशी और विजयोत्सव के ज श्न का माहौल छाया रहा। दूसरी तरफ, करारी हार से भाजपा की छावणी में सन्नाटा और दु:ख का माहौल फैल गया था। अमरेली तहसील पंचायत के परिणाम को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साह देखने को मिला था और यह परिणाम की पटाखे फोडकर कार्यकर्ताओं द्वारा उत्सव मनाया गया। अमरेली की कुल ११ तहसील पंचायत में से पहले कांग्रेस के पास ९ तहसील पंचायत थी और २ तहसील पंचायत पर भाजपा का शासन था, लेकिन भाज पा के पास से दो तहसील पंचायत भी इस बार भी कांग्रेस ने जीत लिया था और सभी तहसील पंचायत पर कांग्रेस का पंजा छाप दिया था। ११ तहसील पंचायत में से ७ तहसील पंचायत पर निर्विरोध कांग्रेस के उम्मीदवार की पसंदगी हुई थी। जाफराबाद और राजुला तहसील पंचायत भाजपा के पास थी, लेकिन परेश धानाणी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बार काफी मेहनत करके यह दो सीटें भी भाजपा के पास से छीन ली है। राजुला तहसील पंचायत के प्रमुख और उपप्रमुख की आज नियुक्ति की गई थी। तहसील पंचायत भाजपा के पास से कांग्रेस ने छीन लिया है। अमरेली की कुल ११ तहसील पंचायत में से पहले कांग्रेस के पास ९ तहसील पंचायत थी और २ तहसील पंचायत पर भाजपा का शासन था, लेकिन भाजपा के पास से दो तहसील पंचायत भी इस बार भी कांग्रेस ने जीत लिया था और सभी तहसील पंचायत पर कांग्रेस का पंजा छाप दिया था। भाजपा के ३ बागी सदस्यों से कांग्रेस सत्ता पर आयी थी। प्रमुख के तौर पर बंसीबहन लाडुमोर और उपप्रमुख के तौर पर गीताबहन धाखडा की नियुक्ति की गई थी। भाजपा के सदस्यों ने तहसील पंचायत की चैम्बर में नुकसान पहुंचाने पर हंगामा हुआ था। चुनाव प्रक्रिया में नया पुराना होने की वजह से पहले से ही पुलिस का बंदोबस्त किया गया था।

सूरत महानगरपालिका आयोजित मुख्यमंत्री ऐप्रेन्टिसशिप योजना के तहत कोम्युनिटी होल, दिवाली बाग सोसायटी, ऋषभ चार रास्ता, रांदेर रोड, अडाजण पाटीया में ऐप्रेन्टीस भर्ती मेला का आयोजन किया गया। जिसमें पालिका के पदाधिकारी एवं कई महानुभाव हाजिर रहे। कुल 6300 से अधिक आवेदन मिले। सूरत महानगरपालिका द्वारा 450 से अधिक उम्मीदवारों को स्थल पर ही नियुक्ति पत्र दिया गया।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का सूरत में विरोध

सूरत (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण की कवायद में एक और पेंच फंस गया है। सूरत जिले के किसानों ने सोमवार को परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के खिलाफ मेमोरंडम दिया। उल्लेखनीय है कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पहले से ही 14 आपत्तियां दर्ज हैं। किसान नेता जयेश पटेल ने कहा कि परियोजना के लिए 21 गांवों में लगभग 110 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। पटेल ने कहा, %लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन एनवायरमेंटल या सोशल इंपैक्ट असेसमेंट बिना ही लाया गया है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले स्थानीय इकाइयों से भी संपर्क नहीं किया गया था। पटेल ने कहा कानूनी तौर पर जिस जमीन का अधिग्रहण करना होता है, उसके लिए जिला कलेक्टर को मार्केट रेट का ऐलान करना होता है। उन्होंने कहा कि सूरत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अब तक जमीन के मार्केट रेट का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा, %सरकार दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए पर्याप्त जमीन ले चुकी है। अब ऐसी कोई वजह नहीं बनती कि अब हमारी जमीनें फिर से अधिग्रहीत की जाएं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए वेस्टर्न रेलवे के पास पर्याप्त जमीन है। गौरतलब है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए बनी नोडल बॉडी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचआरसीएल) को महाराष्ट्र के पालघर में भूमि अधिग्रहण में दिक्कत हो रही है। पटेल ने कहा हम पालघर में भूमि अधिग्रहण का विरोध करनेवालों से संपर्क में हैं। उनकी तरह ही हम भी अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की गुजरात में भव्य तैयारियां, 1.25 करोड़ शामिल होंगे : शिक्षा मंत्री

अहमदाबाद (ईएमएस)। 21 जून, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के भव्य समारोह की गुजरात में तैयारियां पूर्ण होने को हैं। समग्र विश्व में 21 जून 2015 से प्रति वर्ष नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। गुजरात ने पिछले तीन वर्ष से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया है जिसे सराहा गया। इसी प्रकार आगामी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन होगा।

यह जानकारी देते हुए शिक्षामंत्री भुपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम में गुजरात के करीब 1.25 करोड़ लोग स्वयंभु भाग लेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को विशेष बनाने के लिए इसमे दिव्यांग बालक भी भाग लें, इसका प्रयास अहमदाबाद जिला प्रशासन ने किया है। इस आयोजन के अंतर्गत 750 से 1200 जितने दिव्यांग बालक योग निदर्शन करेंगे जिसे साइलेंट योग के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल समग्र विश्व में 350 दिव्यांग बालकों के योग निदर्शन का रिकॉर्ड है जबकि अहमदाबाद में इस संख्या को 750 से 1200 रखे जाने का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम

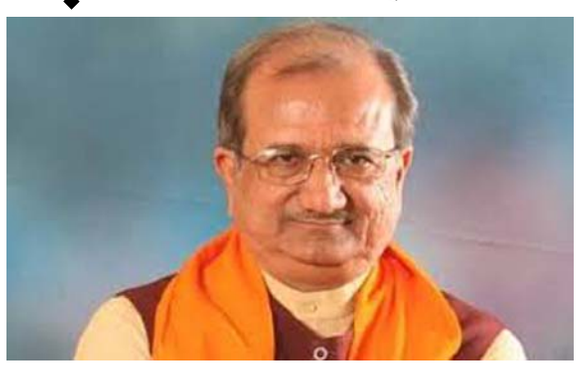

पतंजलि योग संस्था के सहयोग से सरदार पटेल स्टेडियम में होगा जिसमें राज्यपाल ओपी कोहली, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केन्द्रीय कानून, न्याय एवं कॉर्पोरेट अफ्रेर्स राज्य मंत्री पीपी चौधरी, गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी, गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एम.आर. शाह, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश झवेरी, मुख्य सचिव डॉ. जे.एन.सिंह भाग लेंगे। समग्र गुजरात में विभिन्न जिलों से कुल 43,377 केन्द्रों पर भव्यता से योग निदर्शन किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में करीब 4082 गर्भवती महिलाएं और 8732 दिव्यांग बालक भाग लेंगे। इस महोत्सव में पतंजलि योग संस्था के साथ ही श्रीश्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग संस्था, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय, स्वामीनारायण सम्प्रदाय की विभिन्न संस्थाएं और योग से जुड़ीं राज्य की अनेक स्वैच्छिक सेवा संस्थाएं सहयोग कर रही हैं।

तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकरा पलटी, दो लोगों की मौत

वडोदरा (ईएमएस)। हालोल की ओर जा रहे तेज रफ्तार इंडिका कार रोड डिवाइडर से पलटी खाई गई। इस हादसे में दाहोद निवासी दो लोगों की मौत हो गई। जबकि चार लोग घायल हो गए, जिन्हें वडोदरा के सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वडोदरा से हालोल की ओर तेज रफ्तार में जा रही इंडिका कार चालक ने स्टेयरिंग से नियंत्रण गंवा दिया और कार रोड डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। दुर्घटना में दाहोद के भाभर मुहल्ला निवासी 40 वर्षीय विनोद राणा और 45 वर्षीय विशाल मुकुंद बिहारी की मौत हो गई।

म्युनि. की रिकवरी प्रोसेस आशंका और प्रश्नों के घेरे

रोड-रास्ते टूट गये करोड़ों की वसूली सिर्फ नाम की

अहमदाबाद। गत मॉनसून के पहले राउन्ड के सामान्य बारिश में शहरभर के अधिकतर रास्ते टूट गये थे। करोड़ों रुपये के खर्च से तैयार किए गए रास्ते जगह-जगह टूटने पर राज्यभर में रोड घोटाले से भारी हंगामा हुआ था। गांधीनगर तक इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होने पर तथा हाईकोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लेने पर म्युनिसिपल सत्ताधीशों ने पूरे घोटाले की विजिलन्स जांच कराना अनिवार्य हो गया था। अब म्युनिसिपल प्रशासन द्वारा टूटे हुए रोड के कॉन्ट्राक्टरों के पास से नुकसान की रकम वसूलने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि, शहर में रोड-रास्ते टूट गये थे करोड़ों रुपये की वसूली सिर्फ नाम की हो रही है यानी कि दोषी कॉन्ट्राक्टरों के पास से सिर्फ ६.५० करोड़ रुपये ही वसूलने का काम हो रहा है, वास्तव में नुकसान का आंकड़ा करोड़ों रुपये का हो रहा है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, गत मंगलवार को प्रशासन द्वारा विजिलन्स जांच के दूसरे दौर के तहत २० म्युनिसिपल इंजीनियर को नोटिस भेजा गया था। अब सत्ताधीशों ने रोड टूटने के मामले में दोषी साबित हुए कॉन्ट्राक्टर के पास से ६.५० करोड़ रुपये की वसूल करने की दिशा में काम शुरू किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की विजिलन्स जांच के प्रथम दौर में टूटे हुए ९१ रोड में से ४५ रोड में इंजीनियर विभाग की लापरवाही सामने आने पर टोप के एडिशनल सिटी इंजीनियर सहित कुल २६ इंजीनियरों को विभिन्न रोड के लिए कुल ८१ नोटिस भेजा गया था।

उस समय में जीपी चौधरी, आकाश इन्फ्रास्ट्रक्चर और जेआर. अग्रवाल को तीन वर्ष के लिए ब्लेक लिस्ट किया गया था। इसके पहले गुरुकूल सरकारी आवास से सुभाषचौक तक रोड के रिसरफेसिंग के काम में जेआर. अग्रवाल का घोटाला पकड़ा गया था। फिर भी सत्ताधीशों द्वारा यह कॉन्ट्राक्टरों को सिर्फ एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्ट करके बचाया गया था।

अहमदाबाद शहर में नवरंगपुरा में स्थित बेहरामुंगा स्कूल आश्रम रोड में दिव्यांग बच्चों द्वारा भी योग की प्रेक्टिस की गई थी।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

हथियारधारी गैंग का आतंक परिवार पर हमला करके लूट

अहमदाबाद। शहर में फिर एक बार हथियारधारी लुटेरा गैंग सक्रिय हो गया है। दूरदराज वाले क्षेत्रों को टार्गेट बनाकर गैंग परिवारजनों के साथ मारपीट करके लूट करके फरार हो जाते है। नारोल और सरखेज क्षेत्र में हथियारधारी लुटेरा गैंग की आतंक के बाद अब चांदखेडा क्षेत्र में चड्डी बनियानधारी लुटेरा गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। शहर के चांदखेडा गांव के पीछे स्थित आम्रकुंज बंगले में रविवार को देर रात को हथियार के साथ आये चड्डी बनियानधारी लुटेरा गैंग ने चोरी करके ३० हजार रुपये की मालसामान की लूट करके फरार हो गये थे। परिवारवाले जग जाने पर लुटेरों ने पत्थरबाजी भी की थी।

उधना में दो राउन्ड फायरिंग कर भाग रहे दो व्यक्तियों का फोटा सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। मंगलवार को सूरत के उधना इलाके में फायरिंग कर सनसनी मचा कर मनचले फरार हो गए।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com